P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में नवउदारवादी व्यवस्था एवं प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण

पवन कुमार
रिसर्च स्कॉलर
एस.डी. (पी.जी.)कॉलेज,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

नवउदारवाद मानवीय स्वतन्त्रता का समर्थक है, जो पूँजीवादी विचारधारा पर बल देता है। इसके अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए, अतः यह व्यक्ति के जीवन में राज्य के किसी भी हस्तक्षेप का विरोध करता है। इसके अतिरिक्त समाज के दीन–हीन वर्गों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता जैसे आरक्षण आदि का यह विरोधी है।

मुख्य शब्द : नवउदारवाद, राज्य, व्यक्ति, स्वतन्त्रता, पूँजीवादी विचारधारा, भूमण्डलीकरण।

प्रस्तावना

उदारवाद का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, जिसका मूल अर्थ है स्वतन्त्रता। यह विचारधारा व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में उसकी स्वतन्त्रता का समर्थन करती है, जिससे व्यक्ति का विकास प्रभावित न हो। इस विचारधारा के अनुसार निरंकुश व मनमानी सत्ता व्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाधा होती है। इस प्रकार व्यक्ति को सभी प्रकार की निरंकुशता से मुक्ति दिलाना ही उदारवाद का प्रमुख लक्ष्य है। जॉन लॉक को इस विचारधारा का पिता माना जाता है। इसका केन्द्रीय बिन्दु व्यक्तिवाद है। यह लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य, अन्तर्राष्ट्रीयवाद और विश्व शांति में विश्वास रखती है। उदारवाद को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. प्रारम्भिक या नकारात्मक उदारवाद
2. समकालीन या नवउदारवाद
3. सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद

प्रारम्भिक या नकारात्मक उदारवाद व्यक्तिवाद पर आधारित है, जो पूँजीवादी विचारधारा का समर्थन करता है। यह राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाधक मानता है और व्यक्ति के जीवन में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की माँग करता है। इस प्रकार यह राज्य की भूमिका को नकारात्मक मानता है। इसके मुख्य समर्थक जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेन्थम तथा हरबर्ट स्पेन्सर है।

सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य का समर्थक है, जो समाजवादी विचारधारा पर बल देता है। इसके मुख्य समर्थक जे०एस० मिब्स, टी०एच० ग्रीन, मैकावर तथा लास्की है। यह विचारधारा राज्य को लोक कल्याण का साधन मानते हुए शान्तिपूर्ण और क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करती है।

नवउदारवाद या समकालीन उदारवाद 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में लोकप्रिय हुई। यह अहस्तक्षेप की नीति को लागू करने का समर्थन करती है तथा कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधा मानती है क्योंकि उसमें समाज के प्रतिभाशाली लोगों पर कर लगाकर अयोग्य लोगों का पोषण किया जाता है। यह राज्य के दूर–दूर तक फैले हुए कार्यक्षेत्र को फिर से समेटने का समर्थन करता है। यह ऐसी व्यवस्था की माँग करता है कि जिसमें समाज के समर्थ व साधन सम्पन्न व्यक्तियों को अपनी उन्नति के मार्ग में किसी रूकावट का सामना न करना पड़े। इसके दार्शनिक आधार एफ०ए० हेयर, आईजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिल के चिन्तन में मिलता है। समकालीन विश्व में नवउदारवाद ने निम्नलिखित संकल्पनाओं को जन्म दिया–

1. उदारीकरण,
2. निजीकरण,
3. भूमण्डलीकरण।

उदारीकरण से तात्पर्य प्रत्येक देश द्वारा व्यापार के नियमों के प्रतिबन्धों के सरलीकरण से है, जिससे प्रत्येक देश बिना किसी समस्या के दूसरे देशों में

व्यापार कर सकें। अर्थात् उदारीकरण में व्यापार के लिए सभी पेशों द्वारा नियमों में ढील दी जाती है, जिससे किसी भी देश में व्यापार करने में बाधा उत्पन्न न हो।

उदारीकरण के पश्चात् व्यापार के लिए निजीकरण पर बल दिया गया जिससे सरकारी कम्पनियों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय निजी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उद्‌भव हुआ।

भूमण्डलीकरण आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया का नाम है। इसके द्वारा अधिकांश देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को लगातार खोलते जाते हैं। यह खुलापन केवल व्यापार, निवेश तथा वित्तीय प्रवाह तक सीमित न होकर सेवाओं, प्रौद्योगिकी, सूचनाओं, विचारों तथा व्यक्तियों तक होता है। अर्थात् भूमण्डलीकरण मुक्त बाजार की स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की एकीकरण की प्रक्रिया है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में अनेक देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। इन्हें ''तीसरी दुनिया'' के देश कहा गया। भारत भी इनमें से एक है। आजादी के समय ये देश विकास के सन्दर्भ में पिछड़े हुए थे तथा ये इतने परिपक्व भी नहीं थे कि अपने दम पर विकास कर सके। भारत में आजादी से पहले भी 1944 के बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान में पब्लिक सेक्टर के प्रभुत्व वाले पूँजीवादी विकास के रास्ते की बात की गई। आजादी के बाद भारत के पूँजीपति वर्ग द्वारा इसी ब्लू प्रिन्ट के रास्ते को अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें बुनियादी और अवरचनागत उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर बल दिया गया। इस समय दुनिया में समाजवाद अपनी चरम अवस्था पर था इसलिए भारत ने पूँजीवादी व्यवस्था के साथ–साथ समाजवाद को अपनाने पर भी बल दिया।

पूँजीवाद के परिणामस्वरूप 1951 से 1965 तक भारत ने बुनियादी और अवरचनागत क्षेत्रों में तो विकास किया, परन्तु 1960 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी पड़ गई और 1970 के दशक तक अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब हो गई। इस प्रकार विकास के लिए बनाया गया पूँजीवादी मॉडल भारत के हितों की पूर्ति नहीं कर पाया। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार परिवर्तन हो रहे थे, जिन्हें अपनाए बिना भारत भी अपने विकास के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता था।

अतः भारत को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हो रहे परिवर्तनों जैसे उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण को अपनाना पड़ा। भारत में इसकी शुरूआत 1980 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा की गई, जिसके द्वारा 30 उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता हटाई गई तथा आयात पर प्रतिबन्धों में छूट दी गई।

भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नवउदारवादी नीतियों की शुरूआत नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह द्वारा की गई। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा भारतीय विदेशी मुद्रा भण्डार घटकर लगभग 1 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया था जो केवल दो सप्ताह तक आयात करने में सक्षम था। ऐसी स्थिति भारत विदेशी कर्ज में डिफॉल्टर की स्थिति में आ गया था। इस समय भारत का राजकोषीय घाटा जी०डी०पी० के 10 प्रतिशत के आस–पास पहुँच गया था, जिसके लिए विदेशों से कर्ज लेना पड़ा और यह 1990–1991 तक बढ़कर 59 मिलियन डॉलर हो गया। 1990 के खाड़ी–युद्ध के कारण तेल की कीमतों ने इस समस्या को और भी ज्यादा गम्भीर कर दिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था की इस गम्भीर स्थिति ने नेहरूवादी समाजवाद को त्यागकर नवउदारवादी नीतियों को अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा कल्याण योजनाओं में भारी कटौती की गई तथा संरचनागत सुधार के लिए 18 क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में लाईसेंस की सुविधा को समाप्त कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 8 कर दी गई। इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू की गई तथा विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए आयात शुल्कों में भारी कटौती की गई।

इस प्रकार नवउदारवाद का प्रभाव व्यापार के साथ–साथ संस्कृति तथा जातीय सम्बन्धों पर भी पड़ा जिससे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्व कमजोर हुए और विभिन्न जातियों में निकटता आई और उनके अर्न्तसम्बन्ध कुछ नरम हुए।

भारत में नवउदारवाद पश्चिमी उदारवाद तथा गाँधीवादी विचारधारा का मिश्रण है, जिसमें प्रभावशाली वर्ग के विकास के साथ–साथ समाज के कमजोर वर्गों के विकास पर भी बल दिया अर्थात् भारतीय नवउदारवाद सामाजिक न्याय तथा व्यक्तिगत न्याय का मिश्रण है। गाँधीवादी सिद्धान्तों जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय तथा न्यासिता द्वारा भी सामाजिक न्याय की स्थापना पर भी बल दिया गया, जिसमें गरीब व्यक्तियों का भी विकास निहित था। वर्तमान समय में विभिन्न सरकारों द्वारा गरीब वर्ग को आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान कर भी सामाजिक न्याय पर बल दिया जा रहा है।

भारत में नवउदारवादी नीतियों की शुरूआत के लगभग 27 वर्ष पूरे हो चुके है, जिसके परिणामस्वरूप भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के शासक वर्ग बुद्धिजीवियों अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों ने इस पर खुशी का माहौल व्यक्त किया तथा देश के विभिन्न टी०वी० चैनलों, अखबारों तथा बुद्धिजीवियों ने उपरोक्त सुधारों की प्रशंसा की और यह माना गया कि नवउदारवाद के फलस्वरूप देश के विकास के साथ–साथ समाज के प्रत्येक वर्ग का भी विकास हुआ है। परन्तु इस बात पर भी बल दिया कि नौकरशाही, राजनैतिक भ्रष्टाचार पर यदि नियंत्रण कर लिया जाए तो देश का विकास और ज्यादा हो सकता है। जबकि देश के कुछ वामपंथी लगातार नवउदारवादी नीतियों के आलोचक भी रहे हैं और वे मानते हैं कि भारत में इस व्यवस्था के लागू होने से पहले समाज में समानता थी और समाज खुशहाल था। इससे समाज का अमीर वर्ग अमीर होता चला गया और गरीब वर्ग गरीब होता चला गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था के जी०डी०पी० के आंकलन से ज्ञात होता है कि जी०डी०पी० का 52 प्रतिशत से भी

अधिक सेवा क्षेत्र से आता है तथा उद्योगों का योगदान 30 प्रतिशत से भी नीचे है। वह कृषि का योगदान 17 प्रतिशत के आस–पास है। अतः स्पष्ट है कि नवउदारवाद नीति लागू होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का दबदबा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 1991 से 2013 के बीच भारत में 30 करोड़ रोजगारों की आवश्यकता थी, जिसमें से केवल 14 करोड़ लोगों को ही काम मिला है और जिनको काम मिला उनमें से 60 प्रतिशत को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता। कुल रोजगार में सिर्फ 7 प्रतिशत ही संगठित क्षेत्र में है बाकी 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है जिनका न कोई निश्चित मासिक वेतन है और न ही अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ उन्हें प्राप्त है।

नवउदारवाद के समर्थक आम लोगों को रोजगार देने की बात करते है जबकि उदारीकरण के 27 वर्षों के दौरान रोजगार विहीन विकास का मुख्य लाभ बड़े पूँजीपति घराने को हुआ है। आँकड़ों के अनुसार 1990 के दशक के मध्य भारत में सिर्फ दो अरबपति थे जबकि 2016 तक अरबपतियों की संख्या 111 तक पहुँच गई है और इस दौरान अरबपतियों की सम्पत्ति जी०डी०पी० 1 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल सम्पदा का 50 फीसदी हिस्सा सिर्फ 1 प्रतिशत लोगों के पास इकट्ठा हो गया है। बड़े पूँजीपतियों के अलावा मध्य वर्ग के छोटे तबके ने भी नवउदारवादी नीतियों का फायदा उठाया है। इसमें कॉरपोरेटर सेक्टर में काम करने वाले पेशेवरों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, पत्रकारों, सरकारी नौकरी में कार्यरत उच्च अधिकारी, ठेकेदारों, सट्टेबाजों, दलालों को इन नीतियों की वजह से जबरदस्त लाभ हुआ है। जबकि समाज का गरीब वर्ग आज भी दीन हीन जीवन व्यतीत कर रहा है।

भारत में नवउदारवाद के समर्थक मनमोहन सिंह और मोनटेक सिंह अहलूवालिया कहते थे कि जबकि समाज के शीर्ष वर्ग पर सम्पदा इकट्ठा हो जाएगी तो वह धीरे–धीरे समाज के निचले तबकों तक भी पहुँच जाएगी जबकि ऐसा नहीं हुआ है और बहुसंख्यक वर्ग आज भी गरीबी, भूखमरी और अमानवीय हालात में जीने के लिए मजबूर है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उतसा पटनायक के अनुसार नव उदारवाद के दौर में प्रतिव्यक्ति अनाज की उपलब्धता तेजी से घटकर औपनिवेशिक काल से भी नीचे के स्तर पर पहुँच गई है। जबकि नवउदारवाद के समर्थक प्रतिव्यक्ति क्लौरी के स्थान पर मूल्य सूचकांकों का प्रयोग करके आँकड़ों के द्वारा गरीबी कम होती हुई दिखाते है।

विभिन्न आँकड़ों से स्पष्ट है कि नवउदारवाद के दौर में शहरों तथा देहातों दोनों में गरीबी बढ़ी है। 2004 की अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश की 77 फीसदी आबादी 20 रूपए या उससे कम की प्रतिदिन की आमदनी पर गुजारा करती है। इसके अलावा छोटे किसान, छोटे दुकानदार और व्यापारियों की हालात भी नवउदारवादी समय में खराब हुई है। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है, जिसका कारण कहीं न कहीं नवउदारवाद के नतीजे ही है। इस समय खनिज सम्पदा के दोहन से आदिवासी भी प्रभावित हुए है और उनके जंगल, जमीन और जल आदि नष्ट किए गए है। स्पष्ट है कि इन वर्गों की बर्बादी का जिम्मेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के शीर्ष पूँजीपति वर्ग है।

नवउदारवादी स्पष्ट करते हैं कि इन नीतियों के परिणामस्वरूप भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में जबरदस्त वृद्धि हुई है जहाँ 1991 में विदेशी मुद्रा भण्डार 1 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया था वह अब बढ़कर 360 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। यह आँकड़ा भी भ्रामक है क्योंकि इससे यह सच्चाई सामने नहीं आती कि नवउदारवाद के तीन वर्षों को छोड़कर अन्य वर्षों में देश के भुगतान सन्तुलन के चालू खाते में घाटे की स्थिति रही हैं। यदि विदेशी मुद्रा भण्डार में बढ़ोत्तरी हुई है तो विदेशी निवेशकों और ऋणदाताओं ने ज्यादा लाभ कमाने के लिए भारत के शेयर बाजार में निवेश किया है। यह निवेश कब वापस ले लिया जाये इसका कोई भरोसा नहीं है। स्पष्ट है वर्तमान समय में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भण्डार होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों पर निर्भर है।

नवउदारवादी दौर में विकास का मुख्य प्रेरक बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र को दिए जाने वाला कर्ज विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में अत्यधिक निवेश की वजह से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता की स्थिति पैदा हुई है, जिसका लाभ उठाकर बैंकों ने निजी क्षेत्र को बेहताशा ऋण दिए है। जहाँ 1989–90 में बैंक क्रेडिट या जी०डी०पी० का अनुपात 22 प्रतिशत था वहीं यह बढ़कर 50 प्रतिशत से भी ऊपर हो गया है। स्पष्ट है कि बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र में दिए गए ऋण में बढ़ोत्तरी से उनकी अदायगी में डिफाल्ट की सम्भावनाएँ बढ़ी है, जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की अस्थिरता भी बढ़ी है। बैंकों के N.P.A. में बढ़ोत्तरी पिछले पाँच वर्षों में 6 प्रतिशत से बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गयी है। इसके अलावा 2008 से जारी विश्वव्यापी मन्दी की निरन्तरता की वजह से यह अनिश्चितता की ओर बढ़ी है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नवउदारवाद के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था शेयर बाजार में दुनियाभर के सट्टे वालों की पूँजी और बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर टिकी है। इसके अलावा नवउदारवाद के पिछले 25 वर्ष में हिन्दुत्ववादी साम्प्रदायिक फाँसीवादी तत्वों में भी उभार आया है, जिसके प्रमुख कारण निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति खराब होना तथा मध्यम वर्ग का खुशहाल होना है। नवउदारवादी दौर में श्रम कानूनों को पूँजीपतियों के हितों में बनाया गया है। इस प्रकार इस समय दलितों महिलाओं व अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्ग के खिलाफ बर्बर हिंसा की वारदातों में बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही साथ सांस्कृतिक तत्वों पर भी नवउदारवाद की छाप देखने को मिली है, जिसमें साहित्य कला फिल्मों टी०वी० कार्यक्रमों आदि में घोर प्रतिगामी स्त्री विरोधी, धार्मिक कट्टरपंथी और अन्तर्राष्ट्रवादी विचारों मूल्यों और मान्यताऐं छाई हुई है। इस प्रकार नवउदारवाद के परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति और मूल्यों में कमी आई है और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम उभरकर आए है। सकारात्मक रूप में देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है,

जिससे सामाजिक रूढ़िवादिता, धार्मिक अन्धविश्वास, कट्टरता तथा जातीय सम्बन्धों में सरलता आई है, जिससे अर्न्तजातीय विवाह को कुछ रूप में बढ़ावा मिला है। नकारात्मक रूप में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पतन हुआ है। आज देश में स्त्रियों के प्रति हिंसा, बलात्कार, कुकर्म जैसी घटनाएँ बढ़ी है तथा संयुक्त परिवार व्यवस्था ढूँढ रही है और विदेशों की तर्ज पर असंख्य अनाथ आश्रम खोले गए है जिनमें बूढ़े माता–पिता रहने को मजबूर हुए है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य समकालीन विश्व में नवउदारवाद के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई संकल्पनाओं जैसे उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के प्रभावों का अवलोकन करना है।

निष्कर्ष

नवउदारवाद के फलस्वरूप भिन्न देशों की व्यापारिक सीमाओं में खुलापन आया है और राज्य के प्रभाव में कमी आई है। निजीकरण के परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उद्भव हुआ है और छोटे–छोटे लघु और कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और पूरे विश्व में बेरोजगारी दर बढ़ी है। इस प्रकार नवउदारवाद, पूँजीवादी विचारधारा का पोषक है। आज प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में आकर कार्य करने को विवश है और सम्पूर्ण विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में स्थापित हो चुका है और पूरे विश्व का बाजार कुछ पूँजीपति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में आ गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

ओमप्रकाश गाबा : राजनैतिक सिद्धान्त की रूपरेखा, मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, 2010

ग्रेबर, डी० (2009), डाइरेक्ट एक्शन : एन एंथोलॉजी, ऑकलैण्ड : ए.के. प्रेस

हेली, के० (2016), फ़क नुआन्स, सोशियोलॉजिकल

पेक, जे० (2010), जोम्बी नियोलिबरेलिज्म एंड द एम्बीडेक्सट्रस स्टेट, थियोट्रिकल क्रिमिनोलॉजी

क्राउच, सी० (2011), द स्ट्रेंच नॉन–डेथ ऑफ नियोलिबरेलिज्म,ख मलादेन, एम.ए.

बर्नेट, सी० (2005), द कॉन्सोलेशन्स ऑफ नियोलिबरेलिज्म, पॉलिटी प्रेस, जियोफार्म, 36

Robert A. Dohal : Modern Political Analysis (New Delhi, Prentice-Hall 1991)

Michael, J. Sandel (ed.) : Liberalism and its Critics (Oxford, Basil Blackwell, 1984)